Title: Demanded an incease in the amount sanctioned for construction of houses for the SCs, STs and people below poverty line under Indira Awaas Yojana and also demanded regular progress reports from the State Government in this respect.

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और उच्च वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपया मकान बनाने के लिये दिया जाता है लेकिन इतनी कम राशि से किसी इन्सान के रहने के लिये मकान नहीं बन सकता है। इसके पूर्व भी मैं दो बार इस विाय को यहां उठा चुका हूं कि यह राशि 20 हजारे रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये की जाये। यह 20 हजार रुपये की राशि पिछले कई वर्षों से चल रही है जबकि ईंट, सीमेंट, बालू और मज़दूरी का रेट दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसे 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाए। जिस तरह से प्रदेश सरकार से एम.पी.लैड स्कीम के असैसमैन्ट की रिपोर्ट मांगी जाती है, प्रगति प्रतिवेदन मांगा जाता है, उसी तरह से इन्दिरा आवास योजना में भी प्रत्येक राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद ।